



Nagar Nigam Jaipur Heritage


(Purana police Head Quter Badi chopad Hawamahal Jaipur)

E-BID NOTICE NO. 11/2024-25

Enclose in Bid Document

Detailed NIB	
Name & address of the procuring entity	<ul style="list-style-type: none">➤ Nagar Nigam Jaipur heritage.➤ Address: Deputy commissioner (Animal Management) Old PHQ Building, Behind Hawamahal, Badi Chopar, Jaipur.
Subject matter of procurement	नगर निगम हेरिटेज जयपुर शहर से आवारा सूअरो को पकडने एवं पकडे गये सूअरो हेतु खादय आपूर्ति का कार्य कराने हेतु वार्षिक दर संविदा कार्य वर्ष 2024-25
Bid procedure	Single stage Two Part (Envelope) open Competitive E-Bid
Bid evaluation criteria (selection method)	Least Cost Based Selection (LCBS)-L1
Websites for downloading bidding document, corrigendum, addendums, etc.	Websites: www.sppp.rajasthan.gov.in www.eproc.rajasthan.gov.in www.jaipurmcheritage.org
Website for online bid application participation and payment*	<ul style="list-style-type: none">➤ Website: www.jaipurmcheritage.org➤ For participating in the bid the bidder has to apply for this bid and pay the bidding document fee, RISL processing fee online and bid security only.Bidding Document Fees: Rs.590(Five Hundred Ninty Rupee Only) With 18% GST.➤ RISL Processing Fee.: Rs. 500(Five Hundred Rupee Only)➤ Bid Security Rs. 28,000/-
Estimated procurement cost	INR 14 lakh. (Fourteen Lacs Only)
Bid security deposit	INR 28,000 (Twenty Eight Thousand Rupee Only)
Applying bid and maing online payment on nagar nigam portal (www.jaipurmcheritage.org)	Start Date & Time 02-08-2024
Bid Submission on e-procurement portal of GOR (www.eproc.rajasthan.gov.in)	Start Date & Time 02-08-2024 End Date & Time 12-08-2024
Date/Time/place of technical bid opening	Date & Time 13-08-2024 Nagar Nigam Jaipur Heritage
Date/Time/place of Financial bid opening	Will be Intimated later to the technically qualified Bidders
Bid Validity	90 Days from the Bid Opening Date

Note:-Nagar Nigam Jaipur Heritage has decided to receive bid fee, bid security and RISL processing fee online through Nagar Nigam Jaipur Heritage website/portal


Deputy Commissioner
(Animal Management)
Nagar Nigam Jaipur Heritage

कार्यालय उपायुक्त पशु प्रबंधन नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

अल्पकालीन निविदा वर्ष 2024-25


आवारा सूअर पकड़ने के कार्य एवं सूअरों को सूअर बाड़े में खिलाने हेतु खाद्य आपूर्ति की निविदा वर्ष-2024-2025

1. नगर निगम हैरिटेज, जयपुर द्वारा आवारा विचरण करने वाले लगभग 1400 सूअरों को पकड़ने व हटाने एवं खाद्य आपूर्ति के कार्य हेतु ई-प्रोक्यूर्मेंट सिस्टम द्वारा तकनीकी व वित्तीय बीड एक वर्ष के लिए आमन्त्रित की जाती है।
2. संवेदक को नगर निगम हैरिटेज, जयपुर द्वारा उपलब्ध करवाये गये पिजरों द्वारा नगर निगम हैरिटेज क्षेत्र में आवारा विचरण करने वाले आवारा सुअरों को नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा नियुक्त निरीक्षक/प्रभारी/प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार मौके से सुअर पकड़वा कर जामडोली स्थित सुअर बाड़ा में जमा करवाने होंगे एवं इस कार्य हेतु वाहनमय ड्राइवर एवं डीजल निगम द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा।
3. संवेदक द्वारा बिड डॉक्यूमेंट में दर अनुसूची में दर माल एवं सेवा कर एवं अन्य सभी करों सहित प्रस्तुत करनी होगी।
4. संवेदक को मौसम के अनुसार आलू, फूलगोभी, पत्ता गोभी, गाजर, तरबूज, पालक, ककड़ी, घीया, टमाटर, मटर फली, तुरई, कद्दू, बैंगन इत्यादि खाद्य सामग्री जामडोली सूअर बाड़े में आपूर्ति करनी होगी। संवेदक मौसम के अनुसार जो भी खाद्य सामग्री आसानी से उपलब्ध हो, कि आपूर्ति कर सकता है। संवेदक द्वारा समूल खाद्य सामग्री उचित मानकों की होनी चाहिए, सड़ी गली खाद्य सामग्री की आपूर्ति नहीं की जा सकेगी। संवेदक को खाद्य सामग्री इस प्रकार आपूर्ति करनी होगी कि सूअर आसानी से खा सके अर्थात् सब्जियां काट कर छोटे-छोटे टुकड़ों में आपूर्ति करनी होगी।
5. आवारा सूअर को पकड़ने की संख्या घट या बढ़ सकती है।
6. संवेदक को प्रथमतया जयपुर शहर चारदीवारी एवं हैरिटेज जयपुर निगम क्षेत्र को आवारा सुअरों से मुक्त करना होगा व उक्त एरिया में आवारा सुअर विचरण करते पाये जाने पर संवेदक पर 500/-रु. प्रतिदिन प्रति सुअर शास्ती आरोपित की जा सकती है।
7. संवेदक द्वारा सूअर पकड़ते समय, सूअर को रखने में, सूअर के परिवहन करने में पशुओं पर (Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960) एवं इसके अधीन निर्मित पशु क्रूरता संबंधी नियमों का विशेष ध्यान रखना होगा एवं सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी हालत में पशु पर क्रूरता न हो। ऐसे होना पाये जाने पर संबंधित विभाग द्वारा या शिकायतकर्ता द्वारा की गई कार्यवाही के लिए संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा तथा 1000 रु की शास्ती प्रतिदिन आरोपित की जावेगी।
8. संवेदक को शिकायत प्राप्त होने का पश्चात् 24 घण्टे में शिकायतकर्ता से सम्पर्क कर पकड़ने की कार्यवाही करनी होगी एवं आपातकालीन स्थिति से जनहानि होने की आशंका अधिक हो व निगम अधिकारी द्वारा विशिष्ट स्थान से सूअर पकड़ने के आदेश जारी किये हो तो तत्समय समस्या का निस्तारण करना होगा।
9. सूअर पकड़ते समय संवेदक के कर्मचारी को किसी भी प्रकार क्षति होने पर नगर निगम, हैरिटेज जयपुर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। क्षति के लिए संवेदक ही जिम्मेदार होगा।
10. संवेदक द्वारा रखे गये श्रमिक को श्रमिक कल्याण हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लाभ/परिलाभ/वेतन संवेदक को स्वयं देना होगा।

11. निविदा में शामिल न्यूनतम बोली दाता एल-1 द्वारा किसी भी कारण कार्यादेश लेने में विफल होता है तो एल-2 को एल-1 की दर पर कार्यादेश दिये जाने का काउन्टर ऑफ़र दिया जा सकता है।
12. फर्म संवेदक द्वारा कार्य बंद किया जाता है तो प्रतिदिन रूप्ये 1000/- की शास्ती आरोपित की जावेगी।
13. संवेदक द्वारा निर्धारित दर-अनुसूची में प्रस्तुत दर प्रति सूअर सभी टैक्सेज (जीएसटी पृथक) सहित प्रस्तुत करना होगा।
14. यह की एल-1 फर्म संवेदक को दिए गये कार्यादेश के पश्चात् यदि एल-1 द्वारा शिकायतों का निस्तारण समय पर नहीं किया जाता है तो निविदा में भाग लेने वाले एल-2 फर्म द्वारा एल-1 की दर सहमत होने पर एल-2 से नियमानुसार परफॉरमेन्स गारंटी व अमानता राशि जमा करवाकर कार्य करवाया जा सकेगा।
15. संवेदक को आवारा सुअर पकड़ने के कार्य में श्रमिकों हेतु काम में आने वाला आवश्यक सामान स्वयं उपलब्ध करवाना होगा।
16. संवेदक को जयपुर शहर में होने वाले धार्मिक उत्सवों, राष्ट्रीय कार्यक्रमों VIPमूवमेन्ट में प्रभारी व प्रभारी अधिकारी के आदेश से इंतजाम (दिन-रात) व्यवस्था करनी होगी भले ही सुअर पकड़ने का कार्य हो या ना हो ऐसी परिस्थिति में संवेदक को कोई राशि देय नहीं होगी तथा संवेदक को जामडोली सुअर बाड़े में जमा पशु के हिसाब से ही भुगतान किया जायेगा।
17. संवेदक द्वारा समय पर मैन पावर उपलब्ध न कराने पर यदि पिंजरे/निगम संसाधन बिना उपयोग के खड़ा रहा या पुनः गैराज वापस भेजा गया तो प्रत्येक वाहन का उपयोग नहीं करने पर संवेदक फर्म पर 1000/-रु. प्रति वाहन शास्ती आरोपित की जायेगी। मैन पावर उपलब्ध न कराने के कारण यदि किसी शिकायत के निस्तारण में देरी होती है तो उससे उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति के लिए संवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
18. संवेदक द्वारा उपलब्ध मैन पावर द्वारा प्रभारी/प्रभारी अधिकारी के निर्देशों के बावजूद कार्य नहीं करने पर पिंजरा/संसाधन पर होने वाली व्यय राशि जो रु. 1000/- प्रति शिफ्ट की होगी जो बीडर के भुगतान से कटौती की जा सकेगी।
19. संवेदक को सुअर पशु के दूध पीते बच्चे एवं 3 माह के बच्चे के लिए कोई भुगतान देय नहीं होगा।
20. कार्यों में प्रयुक्त सभी मानव शक्ति की व्यवस्था संवेदक को करनी होगी व इस पर होने वाला समस्त व्यय का समय पर भुगतान करना संवेदक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। राजस्थान सरकार, भारत सरकार व अन्य राजकीय संस्थानों द्वारा श्रमिकों के उत्थान हेतु स्थापित नियमों का पालना भी संवेदक को करना होगा।
21. संवेदक को बिल का भुगतान बिल्टियों एवं बिलों पर प्रभारी के प्रमाणीकरण उपरांत ही स्वीकृत दर के अनुसार किया जायेगा।
22. संवेदक द्वारा श्रमिकों/मानव संसाधनों को आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।
23. निविदादाता केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अधीन किसी भी विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है तथा निविदादाता फर्म को भविष्य निधि विभाग/ईएसआई विभाग में पंजीयन के प्रमाणिकर्ता के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे एवं श्रम विभाग के नियमों का पालन करना होगा।
24. संवेदक को दर स्वीकृत के उपरान्त वास्ते अनुबंध निविदा राशि नियमानुसार एवं फर्म की परफोमेंस गारंटी (प्रतिभूति राशि) की राशि ऑन लाईन निगम कोष में जमा करवा कर रसीद की फोटोप्रति कार्यालय में कार्यादेश से 07 दिवस में जमा करवानी होगी।
25. संवेदक को कार्यादेश अवधि एक वर्ष होगी जो कि RTTP Act 2012 & Rules 2013 के अनुसार कार्य संतोषजनक होने पर निविदा की अवधि आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।



26. राज्य सरकार व निगम कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों की पालना निविदादाता को करनी होगी।
27. संवेदक को कार्यादेश देने के पश्चात् 03 दिवस के अन्दर तत्काल कार्य प्रारंभ करना होगा। तथा किसी परिस्थिति में न्यूनतम दरदाता स्वीकृत फर्म द्वारा कार्य संतोषजनक नहीं करने पर निविदा में भाग लेने वाली अन्य फर्मों से कार्य कराने हेतु निगम स्वतंत्र होगा। इन फर्मों द्वारा कार्य न करने पर स्वीकृत दर पर बाजार से व अन्य फर्मों से कार्य करवाया जा सकेगा।
28. संवेदक/फर्म का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर नगर निगम, जयपुर हैरिटेज द्वारा फर्म का अनुबंध अवधि/कार्यादेश/ठेका अवधि को नोटिस देकर बीच में ही समाप्त किया जा सकता है।
29. निविदा की राशि के कार्य प्रतिभूति सम्पादन राशि 5 प्रतिशत होगी।
30. निविदादाता को किसी भी राजकीय संस्था विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन अथवा उपक्रम में वर्तमान में ब्लैक-लिस्टेड/डी-बार अथवा डिफाल्टर घोषित नहीं किया होना चाहिए इस संबंध में 100 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पैपर पर नोटरी से प्रमाणित शपथ-पत्र निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।
31. निविदादाता द्वारा तकनीकी बोली में केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी भी विभाग में समान प्रकृति के कार्य अनुभव का साक्ष्य देना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदादाता की निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी।
32. आर.टी.टी.पी एक्ट 2012 एवं आरटीपीपी रूल्स 2013 में दिए गए निर्देश निविदा में लागू होंगे।
33. निविदादाताओं को निविदा शुल्क, बोली प्रतिभूति एवं प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन नगर निगम, जयपुर वेबसाइट www.jaipurmheritage.org पर submission Date and Time से पूर्व जमा करवा कर उससे प्राप्त होने वाली रसीद को स्कैन करके www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने पर ही निविदा को मान्य किया जायेगा।
34. निविदादाता को निविदा के साथ अपलोड किए गए सभी दस्तावेज मय हस्ताक्षर पुनः Bid submission के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
35. निविदा की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में श्रीमान् आयुक्त महोदय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा व दोनों पक्षों (नगर निगम जयपुर हैरिटेज एवं संवेदक) दोनों को मान्य होगा।
36. नगर निगम जयपुर, हैरिटेज बिना कारण बताए निविदा निरस्त कर सकती है।
37. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर शहर महानगर जयपुर होगा।


उपायुक्त पशु प्रबन्धन
नगर निगम जयपुर हैरिटेज



Nagar Nigam Jaipur Heritage

Technical Bid

S.No.	Discription	Discription of Documents deposit by tenderar
1-	Description of Job	नगर निगम जयपुर हैरिटेज शहर से आवारा सूअरो को पकडने एवं खादय आपूर्ति का कार्य कराने हेतु वार्षिक दर संविदा कार्य वर्ष 2024-25
2-	Name of Firm	
3-	Address & Mob No. of Firm	
4-	Email ID of firm	
5-	PANNo. of firm	
6-	RegistrationNo. to ESI& PF Department.	
7-	Registration No of Labour Dept.	
8-	Firm deposit affidavit about firm is not black listed & No financial liabilities are due against firm.	
9-	2% Bid security	
10-	Bidding Document fee. Rs. 590 (Non Refundable) with 18% GST Including. (500+90)	
11-	RISL Processing fees Rs. 500 (Non Refundable)	

Note:-

- 1- Bidder should deposit Bidding document fees, Bid Security and RISL processing fees online to the wesite www.jaipurheritagemc.org. before submission date and time and tender will be accept valid after above receipt scanned copy will be uploaded to the www.eproc.rajasthan.gov.in. sales tax clearance & registration certificate is also to be scanned.
- 2- Above Mention Information are Correct according to my Knowledge & Faith and over firm are agree for all trem's & rules of the tender.

WWW.JAIPURHERITAGEMC.ORG

WWW.SPPP.RAJ.NIC.IN

Signature of tenderar
with firm seal



Nagar Nigam Jaipur Heritage

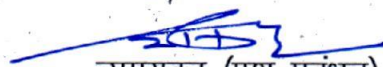
(Purana police Head Quater Badi chopad Hawamahal Jaipur).

Financial-Bid

(दर-अनुसूची)

<u>NIBNo.</u>	कार्य का नाम	दर-प्रति सूअर पकडने एवं पकडै गये सूअर के पॉच दिन की खादय सामग्री की आपूर्ति दर
11	नगर निगम हैरिटेज जयपुर शहर से आवारा सूअरो को पकडने एवं पकडे गये सूअरों हेतु खादय आपूर्ति का कार्य कराने हेतु वार्षिक दर संविदा कार्य वर्ष 2024-25	शब्दों में रूपया अंको में रूपया

निविदादाता


उपायुक्त (पशु प्रबंधन)

नगर निगम जयपुर हैरिटेज

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
 - a. have controlling partners/ shareholders in common; or
 - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 - f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place:

Signature of bidder

Name :

Designation:

Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is _____

The designation and address of the Second Appellate Authority is _____

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
 - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal Noof

Before the (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

.....
.....
..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....
.....
.....

Place

Date

Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Annexure E

Clause 1: Fair Wage Clause

- (a) The Contractor shall pay not less than fair wages/minimum wages to labours engaged by him on the work as revised from time to time by the Government, but the Government shall not be liable to pay any thing extra for it except as stipulated in price escalation clause (clause 45) of the agreement.

Explanation: "Fair Wage" means minimum wages for time or piece work, fixed revised, by the State Government under the Minimum Wages Act, 1948.

- (b) The Contractor shall, notwithstanding the provision of any contract to the contrary, cause to be paid fair wages to labourers indirectly engaged on the work, including any labour engaged by his sub-contractors in connection with the said work as if the labourers have been immediately or directly employed by him.
- (c) In respect of all labourers, immediately or directly employed on the work, for the purpose of the Contractor's part of this agreement, the Contractor shall comply with or cause to be complied with the Public Works Department Contractor's Labour Regulations made, or that may be made by the Government, from time to time, in regard to payment of wages, wage period, deductions from wages, recovery of wages not paid, and unauthorised deductions, maintenance of wages register, wage card, publication of scale of wages and other terms of employment, inspection and submission of periodical returns and other matters of a like nature.
- (d) The Engineer-in-charge shall have the right to deduct from the money due to the Contractor any sum required or estimated to be required for making good the loss suffered by a worker or workers, by reasons of non-fulfilment of the conditions of the contract, for the benefit of the worker or workers, non-payment of wages or of deductions made there from, which are not justified by the terms of the contract, or as a result of non-observance of the aforesaid regulations.
- (e) Vis-à-Vis the Municipal Corporation Jaipur, the Contractor shall be primarily liable for all payments to be made and for the observance of the regulations aforesaid, without prejudice to his right to claim indemnity from his subcontractors,
- (f) The regulations, aforesaid, shall be deemed to be part of this contract and any breach, thereof, shall be breach of the contract.

Clause 2: Contractor to engage technical staff

The Contractor shall engage the technical staff, as follows, on the contract works:-

- (a) For works costing Rs. 100 lac and above- One Graduate Engineer.
- (b) For works costing between Rs. 50 lac to Rs. 100 lac- One qualified diploma holder having experience of not less than 3 years.
- (c) For works costing between Rs. 15 lac and Rs. 50 lac- One qualified diploma holder.

The technical staff should be available at site, whenever required by Engineer-in-charge to take instructions.

Clause 3 :

The Contractor shall comply with the provisions of the Apprenticeship Act, 1961, and the Rules and Orders issued, there under, from time to time. If he fails to do so, his failure will be a breach of contract. The Contractor shall also be liable for any pecuniary liability arising on account of any violation by him of the provisions of the said Act.

Clause 4: Safety Code

The Contractor shall follow the safety code of electricity Strictly.

Clause 5:

Near Relatives barred from tendering

The Contractor shall not be permitted to tender for works in Circle, in which his near relative is posted as Divisional Accountant or as an officer in any capacity between the grades of the Superintending Engineer and Assistant Engineer (both inclusive). He shall also intimate the names of persons, who are working with him in any capacity, or are subsequently employed by him and who are near relatives to any gazetted officer in the Organization/Department. Any breach of this condition by the Contractor would render him liable to be removed from the approved list of contractors of the Department. If such facts is noticed (a) before sanction of tender, his offer shall be declared invalid and earnest money shall be forfeited, (b) after sanction of the tender then the tender sanctioning authority may at his discretion forfeit his earnest money, performance guarantee, security deposit and enlistment deposit and the work/remaining work may allot to any registered contractor on the same rates as per rules.

Note: By the term 'near relative' is meant wife, husband, parents and grand-parents, children and grand children, brothers and sisters, uncles and cousins and their corresponding in-laws.

Clause 6: Retired Gazetted Officers barred for 2 years

No Engineer of Gazetted rank or other Gazetted Officer, employed in Engineering or Administrative duties in an Engineering Department of the Government of Rajasthan, is allowed to work as a Contractor for a period of 2 years of his retirement from Government service without the previous permission of Government of Rajasthan. The contract is liable to be cancelled, if either the Contractor or any of his employees is found, at any time, to be such a person, who had not obtained the permission of Government, as aforesaid, before, submission of the tender or engagement in the contractor's service, as the case may be.

Clause 7: Quality Control

The Municipal Corporation Jaipur shall have right to exercise proper Quality Control measures. The Contractor shall provide all assistance to conduct such tests and shall bear the cost of all tests.

Clause 8:

The work (whether full constructed or not) and all materials, machines, tools and plant, scaffolding,

temporary buildings and other things connected therewith, shall be at the risk of the contractor until the work has been delivered to the Engineer- in -charge, and a certificate from him, to the effect, obtained.

Clause 9: Death of Contractor

Without prejudice to any of the rights or remedies under the contract, if the Contractor dies the legal heirs of the Contractor or the Chief Engineer or duly authorised Engineer shall have the option of terminating the contract without any compensation.

Clause 10 : Force Majeure

Neither party shall be liable to each other, for any loss or damage, occasioned by or arising out of acts of God such as-unprecedented floods, volcanic eruptions, earthquake of other invasion of nature and other acts.

Clause 11: General Discrepancies and errors:

In case of percentage rate tenders, if there is any typographical or clerical error in the rates shown by the department in the "G" Schedule. the rates as given in the basic Schedule of Rates of the Department for the area shall be taken as correct.

Clause 12 : Post payment Audit & Technical Examination:

The Government shall have right to provide a system of per-check of Contractor's bill by a specified Organization, and payment by an Engineer or an Accounts Officer/ Sr. Accounts Officer/ Chief Accounts Officer/ Financial Advisor, as the Government may in its absolute discretion prescribe. Any over-payments/ excess payment detected, as a result of such per-check post-check of Contractor's bill, can be recovered from the contractor's bills in the manner, herein before provided and the Contractor will refund such over/ excess payments.

Clause 13 : Check Measurements:

The department reserves to itself, the right to prescribe a scale of check measurement of work in general, or specific scale for specific works of by other special orders (about which the decision on the department shall be final) Checking of measurement by superior officer shall supersede measurements by the subordinate officer and the former will become the basis of the payment. Any over/excess payment detected, as a result of such check measurement or otherwise at any stage up to the date of completion and the defect removal period specified else-where in this contract, shall be recoverable from the Contractor, as any other dues payable to the Government.

Clause 14: Check Measurements:

The Contractor in course of the work should understand that all materials e.g. stone, bricks, steel and other materials obtainable in the work by dismantling etc. will be considered as the property of the Government and will be disposed off to the best advantage on the Government. As per direction of the Engineer-in-Charge.

Clause 15: Recovery from Contractors:

Whenever any claim against the Contractor for the payment of a sum of money arises out of or under the contract, the Department shall be entitled to recover such sum by appropriation in part or whole of the Performance Guarantee and / or Security Deposit. Security Deposit at the time of enlistment of the Contractor. In the event of the security being insufficient, or if no security has been taken, thereafter, may become due to the Contractor, under this or any other contract with the Governor of Rajasthan. Should this sum be not sufficient to cover the full amount recoverable the Contractor shall pay to the Department on demand the balance remaining dues.

The department shall, further, have the right to affect such recoveries under Public Demands Recovery Act.

Clause 16: Jurisdiction of Court:

In the event of any dispute arising between the parties hereto, in respect or any of the matters comprised in this agreement, the same shall be settled by a competent court having jurisdiction over the place, where agreement is executed any by no other court, after completion of proceedings under Clause 23 of this contract.